>

Title: Regarding unemployment in Maharashtra due to alleged shifting of industrial units out of state including Voltas Plant at Varora, Maharashtra.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बड़े-बड़े उद्योग राज्य सरकार की विशेष विनती पर स्थापित होते हैं। कालांतर में, राज्य सरकार की सुविधाएं प्राप्त कर या करने हेतु जो सहूलियतें मिलती हैं, उन्हें लेकर उद्योग बंद करने की जो प्रथा बनती जा रही है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कई राज्य ऐसे हैं जो अपने यहां उद्योग लाने के लिए करों में रियायत देकर उद्योगों की स्थापना करने की विनती करते हैं और उद्योग वहां स्थापित होते भी हैं, लेकिन कर सहूलियत की कालावधि समाप्त होने के बाद उद्योग बंद करने की जो प्रथा बन गई है, इस वजह से उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके बेवक्त रिटायर होने या बेरोजगार होने की समस्या सामने आ रही है। मेरे क्षेत्र वरोड़ा में एक वोल्टास कम्पनी का रेफ्रीजरेटर्स का कारखाना था, जिसे उन्होंने मल्टीनेशनल कम्पनी इलैक्ट्रोलक्स को बेच दिया। उसे बेचने से पहले, वहां करीब 1500 मजदूर काम करते थे, उसमें से उन्होंने 700 लोगों को वीआरएस दे दिया - वहां मजदूर कम कर दिए गए, एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया। अब इलेक्ट्रोलक्स कम्पनी ने भी उसे विडियोकॉन कम्पनी ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्टेट मैटर है।

श्री हंसराज गं. अहीर : सर, स्टेट मैटर नहीं है, मल्टीनेशनल कम्पनियों के जो कारनामें चल रहे हैं, उनके बारे में मैं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप डिमांड क्या कर रहे हैं?

श्री हंसराज गं. अहीर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें मदद कर रही है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करता हूं कि इलैक्ट्रोलक्स कम्पनी, जो विडियोकॉन को बेची गई है, विडियोकॉन कम्पनी ने वहां पूरा संयंत्र बंद कर दिया है और इस वजह से करीब 700 लोगों की असमय बेरोजगारी की नौबत आई है। ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि यह जो पद्धति चल पड़ी है कि किसी स्टेट में कुछ रियायतें प्राप्त करके, वे अपनी इंडस्ट्री वहां से उठा कर उत्तरांचल के काशीपुर में ले जा रहे हैं, ताकि वहां की सरकार से रियायतें ले सकें। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है कि राज्यों में उद्योग लगाने के लिए जिस तरह की प्रथा बनती जा रही है, इसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और गरीब लोगों को बेरोजगार होने से बचाए।